विचार बिन्दु

हम यहाँ किसी विशेष कारण से हैं। इसीलिए अपने भूत का कैदी बनना छोड़िये। अपने भविष्य के निर्माता बनिए। –रोबिन शर्मा

युवाओं के सपनों को उड़ान देता डिजिफैस्ट ग्लोबल समिट

राजस्थान के सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग द्वारा जयपुर में आयोजित राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट इस मायने में महत्वपूर्ण आयोजन हो जाता है कि डिजिटल क्रांति और एआई के युग में समय के साथ चलतू हुए युवा सपनों की उड़ान को बेहतर अवसर सरकार द्वारा उपलब्ध कराये हैं। इस दौरान जहां जयपुर में बड़ा डेटा सेंटर स्थापना की राह प्रशस्त हुई है वहीं 200 करोड़ रुपए के निवेश की संभावनाएं उभर कर आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरगामी सोच का ही परिणाम रहा कि ग्लोबल समिट मात्र औपचारिकता बनकर रहने के स्थान पर ठोस परिणाम प्राप्त करने में सफल रहा है। युवाओं और तकनीक के प्रति मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि आयोजन के पहले से वे इसकी सफलता को लेकर गंभीर रहे और समय समय पर आयोजन तैयारियों की ना केवल समीक्षा की अपितु आयोजन को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आयोजन देश-दुनिया के सामने राजस्थान को आईटी सेक्टर का भी निवेश का बड़ा केन्द्र बनाने की दिशा में अग्रगामी कदम सिद्ध हुआ है साथ ही युवाओं, एमएसएमई सेक्टर, स्टार्टअप्स के लिए बेहतर अवसर सिद्ध हुआ। आयोजन के माध्यम से यह भी समझाने का प्रयास किया गया कि डिजिटल युग में डेटा संपदा का स्थान लेता जा रहा है। आज डेटा का जमाना आ गया है और डेटा विश्लेषण से भावी का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है।

आयोजन की सफलता को इसी से आंका जा सकता है कि केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केन्द्र सरकार ने राजस्थान को टेक्नोलॉजी, एआई कर बड़ा हब बनाने का रोडमेप तैयार किया है। देश के 10 लाख युवाओं को एआई स्किलिंग ट्रेनिंग देने की शुरुआत भी राजस्थान की राजधानी जयपुर से ही की गई। गूगल के साथ जो एमओयू संपन्न हुआ है उसके दूरगामी लाभ प्रदेश और प्रदेश के युवाओं, एन्टरप्रोन्योर, एमएसइएमई सहित वासियों को मिलने वाला है। एमाओयू के अनुसार गूगल की एक टीम राजस्थान में सक्रिय रहकर कार्य करेगीं। इस आयोजन का एक और बड़ा सार्थक परिणाम यह भी सामने आने वाला है कि सरकारी अधिकारियों से लेकर छात्रों, संस्थानों, स्टार्टअप्स, आदि-आदि के लिए लार्ज स्केल पर स्किलिंग प्रशिक्षण आदि की बेहतरीन विश्वस्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी।

> **साइबर अपराधियों के लाख प्रयासों के बावजूद हौसले बुलंद है। ऐसे लिट्रेसी समय की मांग व आवश्यकता है। कहने का अर्थ यह है कि डिजिटल क्रांति और एआई दुधारी तलवार का काम करती है और इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को देखते हुए ही सरकार गंभीर प्रयास करने जा रही है। एआई-एमएल पॉलिसी निश्चित रुप से ई गवर्नेंस से लेकर रोजगार के अवसरों तक उपयोगी सिद्ध होगी।**

राजस्थान के मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने सही ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार एंटरप्रेन्योरशिप में एआई के उपयोग को बढ़ावा दे रही है और गुड गवर्नेंस में एआई के सटीक उपयोग की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने एआई-एमएल पॉलिसी 2026, आई स्टार्ट एलएमएस, राजस्थान एवीजीसी-एक्सआर पोर्टल तथा राजस्थान एआई पोर्टल को लॉन्च किया है। तीन दिन चले राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट में निवेशक फाउंडर बैठकों, पिच सत्रों और बैठकों के माध्यम से 200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की संभावनाएं बनी। राजस्थान सरकार ने भी पहल करते हुए स्टार्टअप्स में सह-निवेश करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स की घोषणा की। समिट के माध्यम से 100 से अधिक स्टार्टअप्स को मेंटरशिप कार्यक्रमों में शामिल किया गया। 8,867 से अधिक प्रतिभागियों के साथ कॉमिककॉन ने राजस्थान को रचनात्मक उद्योगों, गेमिंग और डिजिटल स्टोरीटेलिंग के उभरते केंद्र के रूप में स्थापित किया।

राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एआई और डिजिटल लिट्रेसी पर जोर देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि राजस्थान की ही बात करें तो प्रदेश में साढे छह करोड़ मोबाइल उपयोगकर्ता है ओर एक मोटे अनुमान के अनुसार 81 हजार करोड़ रु. की लेनदेन प्रति माह यूपीआई प्लेटफार्म के माध्यम से हो रहा है। साइबर अपराधियों के लाख प्रयासों के बावजूद हौसले बुलंद है। ऐसे लिट्रेसी समय की मांग व आवश्यकता है। कहने का अर्थ यह है कि डिजिटल क्रांति और एआई दुधारी तलवार का काम करती है और इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को देखते हुए ही सरकार गंभीर प्रयास करने जा रही है। एआई-एमएल पॉलिसी निश्चित रुप से ई गवर्नेंस से लेकर रोजगार के अवसरों तक उपयोगी सिद्ध होगी।

आयोजन की खास बात यह है कि डिजिटल युग और एआई से जुड़े सभी संभावित क्षेत्रों के विशेषज्ञों और लाभार्थियों को साझा मंच उपलब्ध कराया गया और इसका परिणाम यह रहा कि अनुभवों को साझा करने और जिज्ञासाओं के निराकरण का अवसर प्राप्त हो सका। इस तरह के आयोजनों निश्चित रुप से दीर्घकालीन परिणाम देने वाले होते हैं और भविष्य की भूमिका भी लिखते हैं। निश्चित रुप से यह आयोजन युवाओं, स्टार्ट अप्स, उद्यमियों, एसएएमई सेक्टर्स आदि के साथ ही भावी पीढी यानी कि विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध तो हुआ ही हैं क्योंकि निवेश और निर्णयों को धरातल पर आने से राजस्थान और यहां के युवाओं को सुनहरी राह मिल सकेगी।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(वरिष्ठ लेखक)

राशिफल शुक्रवार 9 जनवरी, 2026

पंडित अनिल शर्मा

माघ मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दिन 1:41 तक, शोभन योग सायं 4:55 तक, विष्टि करण सायं 7:45 तक, चन्द्रमा आज कन्या राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-धनु, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-धनु, बुध-धनु, गुरू-मिथुन, शुक्र-धनु, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज रवियोग दिन 1:41 तक है। भद्रा प्रात: 7:06 से सायं 7:45 तक रहेगी।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:40 तक, लाभ-अमृत 8:40 से 11:16 तक, शुभ 12:34 से 1:52 तक, 7:21 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:21, सूर्यास्त 5:46

मेष
परिवार में चल रहे आपसी मतभेद दूर होने लगेंगे। आज अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। चलते कार्यों का विस्तार होगा।

वृष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

मिथुन
घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

कर्क
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

सिंह
आर्थिक मामलों में बनाए रखना ठीक रहेगा। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। व्यावसायिक मामलों में दुविधा बनी रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी।

तुला
व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। घर-गृहस्थी के खर्चों में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

वृश्चिक
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक परेशानियां दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

मकर
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आज धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक पारिवारिक खर्चों में नियंत्रण रखें।

कुंभ
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। आज नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। यात्रा में दुर्घटना का भय है।

मीन
परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सरकार की जनहितकारी सोच से 12 किमी का फासला घटकर 2 किमी हुआ

भौगोलिक दूरी कम हुई, सरकार और पब्लिक साथ कदमताल कर विकास के पथ पर अग्रसर

नवधा परदेशी

जनजाति अंचल केवल भौगोलिक इकाई नहीं होता, वह अपने भीतर संघर्ष, धैर्य और सदियों पुरानी जीवनशैली को समेटे रहता है। राजस्थान का जनजाति जिला प्रतापगढ़ भी ऐसा ही अंचल है, जहाँ पहाड़, नाले, नदी और कच्चे रास्ते लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। यहाँ विकास की राहें केवल योजनाओं से नहीं बल्कि ज़मीन पर उतरे छोटे-छोटे प्रयासों से बनती हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राज्य सरकार जनजाति क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। सरकार यह जानती है की जनजाति अंचल में विकास का अर्थ केवल इमारतें या सड़कें नहीं होता, बल्कि यह जीवन को सरल बनाने का प्रयास होता है। इसी सोच का परिणाम है माण्डवी-पारसोला रोड से सखीखेड़ा सड़क पर सूकली नदी पर निर्मित पुलिया, जो कागज़ों में भले ही एक सामान्य निर्माण कार्य प्रतीत होती हो लेकिन हकीकत में यह कई लोगों के जीवन में स्थायी परिवर्तन लेकर आई है।

> ■ **केवल किलोमीटर की नहीं, मिटी समय, श्रम और अवसरों की दूरी**

प्रतापगढ़ जिले की विषम भौगोलिक संरचना वर्षों से यहाँ के निवासियों के लिए चुनौती रही है। जिले में माण्डवी पारसोला रोड़ से सखीखेड़ा सड़क पर सूकली नदी पर 4 करोड़ रुपये की लागत से पुल निर्माण किया गया है । पहले लोगों को पारसोला, साबला, डूंगरपुर या आसपुर पहुँचने के लिए 10-12 किलोमीटर का लंबा, घुमावदार और थकाने वाला मार्ग तय करना पड़ता था। यह दूरी केवल किलोमीटर की नहीं थी बल्कि समय, श्रम और अवसरों की भी दूरी थी। ग्राम पंचायत गाडरियावास, केसरपुरा, विजाणिया और जवाहरनगर के गाँवों व फलों के लोगों के लिए यह पुलिया वरदान साबित हुई है। अब वही रास्ता मात्र 2 किलोमीटर में सिमट गया है। जो यात्रा पहले मजबूरी थी, अब सुविधा बन गई है।

पुलिया का प्रभाव केवल आवागमन तक सीमित नहीं है। यह किसानों के लिए अपने उत्पाद को बाज़ार तक समय पर पहुँचाने का माध्यम है, विद्यार्थियों के लिए स्कूल-कॉलेज तक आसान पहुँच का रास्ता है और बीमारों के लिए अस्पताल तक शीघ्र पहुचने के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए यह सुविधा सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी है तो युवाओं के लिए रोजगार और भविष्य की संभावनाओं से। यह केवल एक पुलिया की कहानी है, जनजाति क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किया गया हर एक विकास कार्य सफलता और विकास की अनोखी कहानी अपने में समेटे हुए है।

सूकली नदी पर बनी यह पुलिया उसी सोच की मिसाल है, जहाँ सरकार की संवेदनशीलता और ज़मीनी ज़रूरतें एक-दूसरे से जुड़ती हैं। यह पुलिया बताती है कि जब नीतियाँ जनजाति जीवन की धरातल की वास्तविकताओं को समझकर बनाई जाती हैं, तब ख्वाब जैसा परिवर्तन केवल साकार ही नहीं देता, दिलों में समा भी होता है। राज्य सरकार के द्वारा जनजाति क्षेत्र के लिए किए गए विकास कार्य एवं लिए गए नीतिगत जनकल्याणकारी निर्णय जनजाति अंचल में आने वाले वर्षों के लिए न केवल विकास, सुविधा और विश्वास की नींव मजबूत कर रहे हैं बल्कि समावेशी सुप्रशासन और सरकार और जन के बीच के विश्वास और वादों को निभाने की नई इबारत लिख रहे हैं जो पुल की इमारत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है।

–नवधा परदेशी,
एपीआरओ, बांसवाड़ा

शैक्षणिक संस्थानों में आवारा कुत्ते बनाम आवारा मानव तंत्र

प्रो. अशोक कुमार

किसी भी शैक्षणिक संस्थान की आत्मा उसका शांत और अनुशासित वातावरण होता है। हाल के वर्षों में विश्वविद्यालयों के भीतर दो प्रकार की चुनौतियाँ उभर कर सामने आई हैं: पहली, भौतिक सुरक्षा का खतरा (जैसे आवारा कुत्तों का आतंक) और दूसरी, वैचारिक एवं व्यवस्थागत सुरक्षा का खतरा (बाहरी तत्वों का हस्तक्षेप)। जब विश्वविद्यालय प्रशासन कुत्तों के प्रबंधन के लिए समितियाँ बनाता है और कड़े नियम लागू करता है, तो वही सक्रियता उन मानवीय तत्वों के खिलाफ क्यों नहीं दिखती जो कैंपस की शांति को भंग करते हैं? यह प्रश्न केवल सुरक्षा का नहीं, बल्कि प्रशासनिक इच्छाशक्ति का है।

1. पशु कल्याण और सार्वजनिक सुरक्षा का संतुलन

सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर यह स्पष्ट किया है कि आवारा कुत्तों का प्रबंधन पशु जन्म नियंत्रण नियमों के तहत होना चाहिए। कैंपस में कुत्तों के लिए विशेष समितियां इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि वे मूक प्राणी हैं, उनके व्यवहार का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता और वे रेबीज जैसी घातक बीमारियों के वाहक हो सकते हैं। प्रशासन यहाँ सार्वजनिक सुरक्षा के तर्क को प्राथमिकता देता है, जो कि सही भी है। लेकिन क्या वही सुरक्षा का तर्क तब लागू नहीं होता जब बाहरी राजनीतिक तत्व कैंपस में घुसकर छात्रों को डराते-धमकाते हैं या शैक्षणिक माहौल को दूषित करते हैं?

2. ''अवांछित मानवीय हस्तक्षेप'' की जटिलता

कुत्तों को हटाना एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन बाहरी व्यक्तियों या 'राजनीतिक तत्वों' को रोकना एक जटिल कानूनी और राजनीतिक मुद्दा बन जाता है।

संवैधानिक अधिकार बनाम संस्थान के नियम: भारत का संविधान अनुच्छेद 19 के तहत निर्बाध आवाजाही की स्वतंत्रता देता है। लेकिन शिक्षण संस्थान 'निषिद्ध क्षेत्र' की श्रेणी में आते हैं। प्रशासन के पास यह अधिकार है कि वह बिना अनुमति प्रवेश को अनाधिकार प्रवेश माने।

3. प्रोक्टोरियल बोर्ड की भूमिका: हर विश्वविद्यालय में एक शक्तिशाली प्रोक्टोरियल बोर्ड होता है। इस बोर्ड का प्राथमिक कर्तव्य अनुशासन बनाए रखना और बाहरी तत्वों की पहचान करना है। यदि गेट पर आई-कार्ड चेकिंग अनिवार्य हो और सीसीटीवी का प्रभावी उपयोग किया जाए, तो बाहरी हस्तक्षेप को शून्य किया जा । यह तर्क सटीक है कि इसके लिए किसी नए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मौजूदा नियमों को लागू करने की इच्छाशक्ति चाहिए।

समस्या यहाँ आती है कि विश्वविद्यालय प्रशासन अक्सर राजनीतिक दबाव में होता है। स्थानीय नेता, छात्र संगठनों के पूर्व नेता (जो अब छात्र नहीं हैं) और अन्य बाहरी तत्व अक्सर वोट बैंक या स्थानीय प्रभाव के कारण कैंपस में पैठ बनाए रखते हैं। जब प्रशासन अपने ही बनाए नियमों को लागू करने में विफल रहता है, तो यह आवारा मानवीय तंत्र का रूप ले लेता है, जो आवारा कुत्तों से कहीं अधिक खतरनाक है क्योंकि यह सुव्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण होता है।

4. शैक्षणिक वातावरण बनाम राजनीतिक अड्डा

एक विश्वविद्यालय का प्राथमिक उद्देश्य शोध और शिक्षण है। कैंपस केवल छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित अभयारण्य होना चाहिए। यदि आवारा कुत्तों को छात्रों की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है, तो कैंपस में अशांति फैलाने वाले, धरना-प्रदर्शन करने वाले बाहरी तत्वों को अवांछित क्यों नहीं माना जाता?

बाहरी हस्तक्षेप न केवल पढ़ाई को प्रभावित करता है, बल्कि यह मेधावी छात्रों के मन में असुरक्षा की भावना भी पैदा करता है। केरल और मद्रास उच्च न्यायालयों के फैसले इस बात की पुष्टि करते हैं कि शिक्षण संस्थानों में राजनीतिक गतिविधियों को सीमित किया जाना चाहिए ताकि शैक्षणिक गुणवत्ता बनी रहे।

5. समाधान और मार्ग

इस समस्या के समाधान के लिए डॉग मैनेजमेंट की तर्ज पर विजिटर मैनेजमेंट की आवश्यकता है:

कठोर प्रवेश नीति: गेट पर डिजिटल आई-कार्ड चेकिंग और बायोमेट्रिक एंट्री को बढ़ावा देना।

राजनीतिक अलगाव: छात्र राजनीति और बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींचना।

जवाबदेही: यदि कैंपस में कोई अप्रिय घटना होती है, तो प्रोक्टोरियल बोर्ड और सुरक्षा प्रमुख की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

बाहरी तत्वों द्वारा कैंपस में अशांति फैलाने पर बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के कानूनी प्राथमिकी (एफआइआर) दर्ज होनी चाहिए।

'आवारा कुत्ते' केवल शारीरिक चोट पहुँचा सकते हैं, लेकिन ''आवारा मानवीय तंत्र'' एक पूरी पीढ़ी के भविष्य और संस्थान की साख को काटता है। यदि प्रशासन कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए सक्रियता दिखा सकता है, तो उसे उन तत्वों के खिलाफ भी वैसी ही जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी जो कैंपस की मर्यादा को लांघते हैं। अंततः, एक सुरक्षित कैंपस वही है जहाँ न केवल जानवरों से सुरक्षा हो, बल्कि जहाँ बाहरी अराजकता से भी पूर्ण मुक्ति मिले।

विश्वविद्यालयों को राजनीतिक अखाड़ा बनने से रोकने के लिए अब प्रशासन को अपनी प्रशासनिक इच्छाशक्ति का परिचय देना है।

–प्रो. अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति, कानपुर,
गोरखपुर विश्वविद्यालय एंव
विभागाध्यक्ष राजस्थान
विश्वविद्यालय, जयपुर

बाप तहसील के मोटाई गांव में बिना मान्यता एक घर में चल रहा निजी स्कूल

शिकायत के बाद भी अधिकारी नहीं कर रहे कार्यवाही, ग्रामीणों में रोष

बाप, (निसं)। फलोदी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर से आकर बिना मान्यता प्राप्त अवैध रूप से स्कूल खोलकर छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब छात्र स्कूल से टीसी मांगते हैं, तो उन्हें टीसी नहीं दी जाती है, जिससे उनके भविष्य पर ग्रहण लग जाता है। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि मोटाई गांव में एक घर में अवैध रूप बिना मान्यता प्राप्त से चैंपियन पब्लिक स्कूल संचालित है, लेकिन फिर भी स्कूल बंद करवाने में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

बाप तहसील के मोटाई गांव में चैम्पियन पब्लिक स्कूल नाम से एक घर में अवैध रूप से स्कूल चलाया जा रहा है, जो छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जब बच्चे दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते हैं और टीसी मांगते हैं, तो उन्हें टीसी नहीं दी जाती है, जिससे उनके भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड हो रहा है। ग्रामीणों ने इस अवैध स्कूल के बारे में कई बार शिकायत की है, लेकिन शिक्षा विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि मोटाई में अवैध रूप से चैंपियन पब्लिक स्कूल संचालित है, लेकिन फिर भी स्कूल बंद करने की जहमत नहीं उठाई जा रही है।

> ■ **जब छात्र स्कूल से टीसी मांगते हैं, तो उन्हें टीसी नहीं दी जाती है**

जानकारी के अनुसार बिना मान्यता के मोटाई में चैम्पियन पब्लिक स्कूल संचालन की शिकायतें लंबे समय से की जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि चैम्पियन पब्लिक स्कूल संचालन कर्ता जांच या निरीक्षण करने आने वाले अधिकारियों की आंख में धूल झोंकते हुए बताता है कि वह तो कोचिंग सेंटर चला रहा है। जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि वह बिना मान्यता स्कूल संचालित कर भोले-भाले ग्रामीणों को ठगते हुए उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। शिकायत करने पर संचालक ग्रामीणों को धमकाता है।

ग्रामीण रामरतन विश्नोई सहित कई ग्रामीणों ने बताया कि चैम्पियन पब्लिक स्कूल बिना मान्यता से अवैध रूप से संचालित करने की शिकायतें जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों से करते आ रहे हैं, लेकिन कार्यवाही नही की जा रही।

हिंगलाजदान चारण, सीबीईओ बाप का कहना है कि इसकी जांच कर उच्चाधिकारियों को भेज दी है। इस पर दो साल पहले एफआईआर भी दर्ज हुई थी। वह भी उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट में बता दिया है। कार्यवाही उच्चाधिकारी ही करेंगे।

पूर्णाराम, देव, प्राथमिक जिला शिक्षा अधिकारी फलोदी के अनुसार शिकायत आई है, जांच करवाएंगे। अभी मैं बाहर हूं।

रिटायर लड़ाकू विमान मिग-21 बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगा

बीकानेर, (निसं)। यहां 2025 में नाल बेस से भारतीय वायुसेना से रिटायर हुआ लड़ाकू विमान मिग-21 अब स्कूली बच्चों और युवाओं के लिए सेना में जाने की प्रेरणा बनेगा। इसका एयर फ्रेम श्रीडूंगरगढ़ तहसील के बिग्गाबास रामसरा गांव के कैप्टन चंद्र चौधरी राजकीय सीनियर सेकंडरी स्कूल में रखा जाएगा। प्रदेश में सैनिक स्कूल के बाद यह पहला अवसर होगा, जब एक लड़ाकू विमान का एयर फ्रेम शिक्षा विभाग के किसी सरकारी स्कूल में रखा जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने वॉर ट्रॉफी के रूप में इसकी मंजूरी दे दी है।

शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी मेमोरियल ट्रस्ट के सीताराम सियाग ने बताया कि वायु मुख्यालय ने स्कूल प्रिंसिपल को मेल करके इसकी सूचना दी है। यह एयर फ्रेम बच्चों की शिक्षा के उद्देश्य से दिया जा रहा है। बच्चे मिग-21 के 62 साल की शौर्य गाथा से परिचित हो सकेंगे। युद्धों के दौरान इस विमान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी की याद में मिलने वाला यह चौथा वॉर मेमोरियल होगा। सियाग ने बताया कि इसके लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के प्रयास रहे हैं। बिग्गाबास रामसरा के सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल के पास मंगलवार को एयर हैडक्वार्टर से मेल आया था, जिसकी कॉपी उन्होंने मुझे दी है। मिग-21 के आने से बच्चों को वायु सेना के प्रति रुझान बढ़ेगा।

> ■ **रिटायर लड़ाकू विमान मिग-21 का एयर फ्रेम बिग्गाबास के सरकारी स्कूल में रखा जाएगा**